(c) and (d) SEBI takes appropriate penal action under the SEBI Act, and Rules and Regulations framed thereunder in case market manipulation is established by investigations being carried out "by it. Specifically, SEBI (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade practices relating to Securities Markets) Regulations, 1995 would enable SEBI to take prompt and effective action rigging of share prices.

Liquidity crisis in Corporate Sector

1290. SHRI O. P. KOHLI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item appear ing in the 'Hindustan Times' dated the 15th February, 1996 stating that the total deposit mobilisation by scheduled com mercial banks of the country in the first nine month of 1995-96 has declined by a staggering Rs. 9,000 crore compared to previous year thereby accentuating the liquidity crisis in corporate sector;

(b) if so, the reasons therefor and the steps taken in this regard: and

(c) what are the details of the decline in public and private sector commercial banks during the first nine months of 1995-96?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBI PROSAD PAL): (a) to (c) Reserve Bank of India (RBI) .has reported that the aggregate deposits of scheduled commercial banks showed an increase of Rs. 39181 crore in the first nine months of 1995-96 *i.e.* between March 17, 1995 and December 22, 1995 which is lower than the increase of Rs. 43613 crore in the corresponding period of 1994-95, by Rs. 4432 crores. However, the aggregate deposits of scheduled commercial banks during the 1995-96 so far that is from March 17, 1995 to February 16, 1996 increased by Rs. 45336 crores as compared with Rs. 48232 crores in the com-parable period of 1994-95 thus reducing the decrease to Rs. 2896 crores.

Various measures have been announced by the RBI during the second half of 1995-96 to step up mobilisation of bank deposits. The interest rates on domestic deposits having maturity of over 2 years have been deregulated from October, 1995. The interest rates on deposits under Non-Resident (External) Rupee (NRE) Accounts have been increased in stages from 'not exceeding 8.0 per cent per annum' to 'not exceeding 12.0 per cent per annum' effective October 31, 1995. The average cash reserve ratio (CRR) on outstanding net demand and time liabilities has been reduced from 15.0 per cent to 14.0 per cent. The deposit under Non-Resident, Non-Repa-triable Rupee (NRNR) Accounts and Foreign currency Non-Resident Accounts (Banks)(FCNR) (B) Scheme have been exempted from the maintenance of cash reserve ratio. The average CRR on liabilities under Non-Resident (External) Rupee (NRE) accounts has been reduced from 15.0 pei cent to 10.0 per cent and the incremental deposits under this scheme have been exempted from the maintenance of the average cash reserve ratio.

दूरदर्शन चैनल-3 द्वारा सरकारी नीतियां और कार्यक्रमों का प्रसारण न किया जाना

1291. **श्री अनन्तराम जायसवाल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या सरकार ने दूरदर्शन के सभी चैनलों पर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करने का निर्देश दूरदर्शन को दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच हैं कि दूरदर्शन के चैनल-3 ने राष्ट्रपति के संदेश का प्रसारण नहीं किया और यह चैनल सरकार की नीतियों कार्यक्रमों आदि का कभी भी प्रसारण नहीं करता;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार ने संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी निथत की हैं; और

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) दूरदर्शन द्वारा अपने विभिन्न चैनलों के कार्यक्रमों की अनुसूची स्वयं तैयार की जाती हैं। डीडी-1 और डी-डी 2 पर राष्ट्रपति के संदेश को प्रसारित किया गया था। डीडी-3 की अनुसूची में कार्यक्रम समाचार आधारित तथा अन्य कार्यक्रम भी शामिल हैं जिसमें सरकारी नीतियों और कार्यक्रम कवर किए जाते हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राजकोट स्टाक एक्सचेंज का कार्यकरण उचित न होना

1292. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूमि और विनिमय बोर्ड ने राजकोट स्टाक एक्सचेंज के प्रबंधन और कार्यरकण में कुछ कमियां पायी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सेवी के अध्यक्ष ने इस एक्सचेंज के कार्यकरण और प्रशासनिक रवैये के प्रति अपनी नाराजगी जतायी हैं; और

(घ) इस एक्सचेंज के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबीप्रसाद पाल) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने दिसम्बर, 1995 में संचालित सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज लि., राजकोट की अपनी जांच की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर एक्सचेंज की कार्यप्रणाली में कुछ विसंगतियां पायी। मुख्य विसंगतियां विवरण में दी गई हैं (नीचे देखिए)।

(ग) सेबी के अनुसार, इस संबंध में कुछ भी अभिलेखबद्व नहीं हैं।

(घ) सेबी प्रतिभूति बाजार तथा स्टाक एक्सचेंजों हेतु एक संवैधानिक प्राधिकरण के तौर पर इस एक्सचेंज के कार्यकरण का अनुवीक्षण कर रहा हैं। सेबी एक्सचेंज की जांच पर उचित अनुवर्ती कार्रवाई भी शुरू करेगा।

विवरण

(i) एक्सचेंज की एक उचित संगठनात्मक संरचना नहीं हैं क्योंकि प्रत्येक मुख्य कार्य हेतु अलग विभाग नहीं बनाए गए हैं।

(ii) पिछले एक वर्ष से एक्सचेंज किसी पूर्ण सक्षम कार्यपालक निदेशक तथा सचिव के बिना कार्य कर रहा हैं:

(iii) एक्सचेंज ने वर्ष 1995-96 के लिए अनुशासल नात्मक व्यतिक्रम तथा विवाचन समितियों का गठन अभी तक नहीं किया हैं;

(iv) एक्सचेंज ने बाजार की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र प्रकोष्ठ स्थापित नहीं किया हैं।

Functioning of Peerless Investment Company

1293 SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have received complaints on the functioning of Peerless Investment Company: and

(b) if so, what steps are being contemplated in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBI PROSAD PAL): (a) Yes, Sir.

(b) Peerless General Finance & Investment Company Ltd. (PGFI) is a Residuary Non-Banking Company (RNBC) and its deposit acceptance activities are regulated under the Residuary Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1987 framed under Reserve Bank of India Act, 1934. In order to find out the position of compliance with the provisions of the RNBC Directions, a | detailed inspection was carried out in 1993 when violation of some of the core provisions of the Directions were observed. The Company was asked to take ,, remedial action and accounting aberrations were brought to the notice of the Institute of Chartered Accountants of India. As the compliance with RBI in-